1	2	3
		राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के ध्यान में लाया गया है। श्रम मंत्रियों के सम्मेलन के 40 वें सत्र के अनुवर्ती इस सिफारिश को विभिन्न स्तरों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए पुन: दोहराया गया है। इसी प्रकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गयी है कि जब तक न्यूनतम मजदूरी के भाग के रूप में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध परिवर्ती संघटक का प्रावधान नहीं हो जाता है तब तक दो वर्षों में एक बार मजदूरी की दरों की पुनरीक्षा/संशोधन करें।
4.	प्रबंधन में कर्मवार सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि कर्मकारों और प्रबंधन द्वारा उत्पादकता तथा दक्षता के महत्व एवं प्रबंधन की समस्याएं तथा कर्मकारों के लिए कल्याणकारी उपायों की आवश्यकता की जानकारी की जा सके।	संविधान के 1976 के संशोधन के अनुसार भी, प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता संबंधी आनुक्रमिक योजनाएं शुरू की गयीं और कार्यान्वयन के लिए ली गयीं। जो योजना अब प्रचलन में है उसे ही सरकार ने 30 दिसम्बर, 1993 को अधिसूचित किया। तदुपरान्त, प्रबंध में कर्मचारियों की सहभागिता विधेयक, जिसे इस प्रयोजनार्थ मई, 1990 में पुन: स्थापित किया गया था, की अभी श्रम और कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति से संबंधित विभाग जांच-पड़ताल कर रहा है। फिलहाल, विद्यमान योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जा रही है और समय समय पर प्रबोधन किया जा रहा है।
5.	कई राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने इक्विटी कैपिटल में प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता और श्रमिकों द्वारा रुग्ण औद्योगिक उद्यमों के प्रबंधन के लिए जाने का समर्थन किया।	इस सुझाव पर विचार करते हुए सरकार ने नोट किया कि 24.7.1991 को घोषित की गई नई औद्योगिक नीति में परिकल्पना की गई है कि रुग्ण कम्पनियों को फिर से चालू करने के लिए तैयार किए गए पैकेजों में भाग लेने के लिए श्रमिकों सहकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय नवीकरण निधि के अंतर्गत श्रमिक सहकारियों को शामिल किए जाने पर राष्ट्रीय नवीकरण निधि के अधिकृत प्राधिकारियों द्वारा विचार किया गया और यह सहमति व्यक्त की गई कि कुछ अनुबंधों और शर्तों के अधीन श्रमिक सहकारियों को राष्ट्रीय नवीकरण निधि को सहायता प्रदान की जाएगी।

Sugar Production in Gujarat

1911. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) what is the annual average production of sugar in sugar mills set up in Gujarat as on date;

(b) whether the production of sugar in the State is less than the national average;

(c) if so, what is the total production year-wise during the last three years as against the national average;

(d) what is the total quantity of sugarcane which is being made available to aforesaid sugar mills each year as against the national average; and

(e) what steps have been taken by

Government to bring the present production of sugarcane in Gujarat at par with the national average?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) and (b) The average installed sugar production capacity of a sugar mill in Gujarat State as on 30.6.1995 was 0.451 lakh tonnes as against the national average of 0.2768 lakh tonnes.

(c) and (d) The required information is as under:

Sugar Season	Cane crushed (lakh tonnes)		Sugar Production (Lakh Tonnes)	
	Gujarat	All India	Gujarat	All India
1991-92	67.63	1339.99	7.53	134.11
1992-93	66.25	1029.71	7.51	106.09
1993-94	74.42	982.05	8.26	98.24

(e) The Government have taken/initiated the following measures in order to give a boost to the sugarcane production during 1994-95 sugar season:—

(i) Early-crushing incentives have been announced in the form of higher freesale quota at 72%, as against the normal entitlement of 60% to sugar mills for the production achieved during the period 1.10.1994 to 15.11.1994.

(ii) Late-crushing incentives have been announced in the form of higher freesale quota at 75%, as against the normal entitlement of 60%, to sugar mills for the production achieved during the period 1.5.1995 to 31.7.1995.

(iii) The Statutory Minimum Price (SMP) of sugarcane for 1994-95 season has been raised to Rs. 39.10 per quintal linked to the basic recovery of 8.5% with a premium of Rs. 0.46 for every 0.1% point increase in the recovery above that level upto 10% and Rs. 0.60 for every 0.1% point increase in the recovery above 10%.

(iv) An advance announcement of SMP for 1995-96 season has also been made at Rs. 42.50 per quintal linked to a basic recovery of 8.5%, subject to premium for higher recoveries.

(v) Loans are also being provided from the Sugar Development Fund at concessional rates of interest to sugar factories for undertaking cane development schemes in their areas of production.

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के यूरिया आयात सौदे

1912. **श्री राम जेठमलानी:**
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 मई, 1995 के "दी बिजनेस स्टेन्डर्ड" में "एम.एम.टी.सी. यूरिया इम्पोर्ट कोस्ट्स डालर 40 एम. मोर" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम गैर-सरकारी क्षेत्रों के संस्थानों से सफलतापूर्वक प्रति-स्पर्धा करने में असमर्थ रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकारी क्षेत्र की इन संस्थाओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कीमत अधिक होने के कारण ही देश में वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा किए जा रहे आयात-निर्यात की कीमतों में कमी करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाये जाने पर विचार किया जा रहा है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम्): (क) जी, हां।

(ख) निजी क्षेत्र की किसी भी कम्पनी को यूरिया का आयात करने की अनुमति नहीं दी गयी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। एम.एम.टी.सी. इन वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती है।

Consumer Welfare Funds in various States

1913. **SHRI RAMDAS AGARWAL:**
SHRI ANANT RAM JAISWAL:
SHRI DIGVIJAY SINGH:

Will the Minister of **CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION** be pleased to state: